

37 हजार करोड़ से लखनऊ के सभी गांवों में स्थापित होंगे उद्यम रोजगार के लिए प्रत्येक गांव का बनेगा क्रेडिट प्लान

जासं • लखनऊ : विकास को नई गाथा लिख रहे लखनऊ की पहचान उद्योग नगरी के रूप में भी हो, इसके लिए प्रशासनिक कोशिशें शुरू हो गई हैं। लखनऊ के प्रत्येक गांव में लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए 37,308 करोड़ का क्रेडिट प्लान तैयार किया जा रहा है। प्रशासन ने बैंकों को ग्राम पंचायत वार क्रेडिट प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान डीएम सूर्यपाल गंगवार ने जिले के प्रभारी मंत्री व वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के सामने इस पूरी कार्ययोजना का प्रजेटेशन दिया।

डीएम ने प्रभारी मंत्री को बताया कि राजधानी की प्रत्येक ग्राम पंचायत में न्यूनतम दस छोटी बड़ी इकाइयां स्थापित करने की योजना है। इसके लिए बैंकों को प्रत्येक गांव के लिए लक्ष्य निर्धारित करने को कहा गया है। जो भी लोग रोजगार करने के इच्छुक होंगे उनको आगे बढ़ाने का कार्य होगा। प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रदेश की बन ट्रिलियन डालर इकोनामी हासिल करने के लिए कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना है।

इनेज सिस्टम पर स्थित अतिक्रमण



कलेक्टरेट में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करते वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, साथ में डीएम सूर्यपाल गंगवार व अन्य जागरण

तत्काल हटाया जाए : प्रभारी मंत्री ने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया कि नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत जहां भी इनेज सिस्टम पर अतिक्रमण है उसे तत्काल हटाया जाए। जनप्रतिनिधि भी इस कार्य में सहयोग करें ताकि नालियां प्रभावित न हों। तोड़े जाने पर आने वाले व्यय को भी संबंधित व्यक्ति द्वारा बहन किया जाएगा। मंत्री ने कहा लखनऊ

राजधानी होने के नाते माडल जनपद है इसलिए यहां स्मारक, पर्यटन स्थल एवं निर्माणाधीन पर्यटन स्थलों का रखरखाव बेहतर हो से किया जाए। बैठक में मंत्री के अलावा राज्यसभा सदस्य संजय सेठ, एमएलसी मुकेश शर्मा, उमेश द्विवेदी, राम चंद्र प्रधान और विधायक योगेश शुक्ला, अमेरेश कुमार, ओपी श्रीवास्तव और जय देवी मौजूद थीं।